

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वि०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7
संख्या ¹³⁴⁰/XXVII (7) का०प्र०गै०/०८
देहरादून : दिनांक : 13 मार्च, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- फैक्ट फाइंडिंग जांचों के लिये गठित जांच समितियों में नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन एवं अन्य शर्तों का निर्धारण :-

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जांच आयोग अधिनियम से अलग राज्य सरकार द्वारा कराये जाने वाली फैक्ट फाइंडिंग जांचों के लिये विभिन्न विभागों द्वारा गठित जांच समितियों में मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से इतर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक/सेवारत सरकारी सेवक/असरकारी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर उनके वेतन नियतन एवं अन्य शर्तों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निर्धारण का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। उक्त जांच समितियों में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किये जाने वाले सरकारी सेवकों एवं असरकारी व्यक्तियों का वेतन नियतन एवं अन्य सेवा शर्तें निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) पूर्ण कालिक जांच कार्य के आधार पर पुनर्नियुक्त सरकारी सेवक -

- (1) जांच समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर सेवा निवृत्त सरकारी सेवक को अंतिम आहरित वेतन में से सकल पेंशन (राशिकरण के पूर्व) की धनराशि घटाकर वेतन सी०एस०आर० के अनुच्छेद-520 की व्यवस्थानुसार देय होगा।
- (2) अन्य भत्ते आदि उसी प्रकार देय होंगे जो उसके समकक्ष अन्य अस्थायी सेवकों को या सम्बन्धित सेवक को सेवा निवृत्ति के पूर्व अनुमन्य थे, परन्तु महंगाई भत्ता, उक्त पद के वेतन पर अथवा पेंशन, केवल किसी एक पर ही देय होगा।

- (3) यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के पद की प्रास्थिति के अनुसार देय होंगे।
- (4) सेवा निवृत्ति के पद के वेतनमान के स्लैब तथा शहर की वर्गीकृत श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।
- (5) जांच कार्य हेतु स्टेशनरी एवं जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु टंकण आदि के कार्य के लिये वास्तविक व्यय के बिल के आधार पर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ख) पूर्ण कालिक जांच कार्य के आधार पर नियुक्त सेवारत सरकारी सेवक -

- (1) जांच समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर सेवारत सरकारी सेवक को वह वेतन देय होगा, जो तत्समय उसे प्राप्त हो रहा है।
- (2) यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार सरकारी सेवक के पद की प्रास्थिति के अनुसार अनुमन्य होगा।
- (3) सेवारत पद के वेतनमान के स्लैब तथा शहर की वर्गीकृत श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।
- (4) जांच कार्य हेतु स्टेशनरी एवं जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु टंकण आदि के कार्य के लिये वास्तविक व्यय के बिल के आधार पर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ग) जांच का कार्य पूर्ण कालिक न होने पर अर्थात् यदि कार्य की मात्रा पूर्णकालिक न होकर कुछ दिवसों हेतु कार्य करना हो (सेवारत/सेवानिवृत्त/असरकारी अध्यक्ष/सदस्य हेतु)

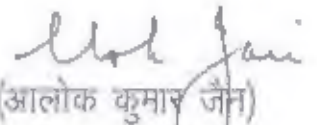
- (1) अंशकालिक पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति के रूप में रु० 2000/- प्रतिदिन की धनराशि मानदेय के रूप में देय होगी। पृथक से कोई धनराशि किसी भी रूप में देय नहीं होगी।
- (2) जांच कार्य हेतु अपने आवास से आने तथा आवास को जाने हेतु यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सेवानिवृत्ति/सेवारत पद की प्रास्थिति के अनुसार राज्य सरकार की दरों के अनुसार देय होगा।

(3) जांच समिति में असरकारी सदस्य होने पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य सरकार के भ्रेणी-। के अधिकारी के समतुल्य अनुमन्य होगा।

(4) जांच कार्य हेतु स्टेशनरी एवं जांच रिपोर्ट तैयार करने हेतु टंकण आदि के कार्य के लिये वास्तविक व्यय के बिल के आधार पर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(5) मुख्यालय से बाहर जांच कार्य हेतु जाने पर जांच समिति के अध्यक्ष/सदस्य को वाहन, सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में होने वाले कार्य के लिए सम्बन्धित विभाग के अनुदान में बजट व्यवस्था करके उसे प्राविधानित बजट से ही वहन किया जाएगा।


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या- 134(1)/XXVII(7)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, उत्तराखण्ड सचिवालय एकक।